

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 70/2022

आरसीएमएस नं. 2022/70

रूपराम पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला
हनुमानगढ़।

—अपीलांत

बनाम

1. औमप्रकाश पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला
हनुमानगढ़।
2. विनोद पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला
हनुमानगढ़।
3. सहायक अभियन्ता जो.वि.एन.एल. गोगामेड़ी तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा।

— रेस्पोंडेंट्स



अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भादरा, दिनांक 07.03.2022, प्र. सं. 66/2021

उपस्थिति:—

श्री विजय कौशिक अभिभाषक अपीलांत

श्री महेश शर्मा अभिभाषक रेस्पों सं० 1 व 2

श्री विजय सिंह कड़वासरा अभिभाषक रेस्पों सं० 3

श्री राजेश कौशिक अभिभाषक रेस्पों सं० 4

निर्णय

दिनांक 22.12.22

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया

Low

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जिसमें कथन किया कि रोही मौजा 8 डीपीएन के खाता सं० 9/7 में कुल 3.036 है० नहरी भूमि प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 5 डीपीएन के खाता संख्या 4/100 के मु. नं. 47 में 2.0240 है० में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा व रोही मौजा चक 2 डीएनके खाता संख्या 15/141 मु. नं. 11 के किला नं. 16, 17, 18, 19, 20, 21 ता 25 की कुल 1.985 है० नहरी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 2416/9925 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 2 डीपीएन के खाता संख्या 16/14 के मु. नं. 27 के किला नं. 5, 6 की 0.5060 है० भूमि प्रतिवादी सं० 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। पहले यह भूमि श्योचन्द के नाम थी। श्योचन्द के फौत होने के बाद भूमि परिवार का कर्ता होने के कारण प्रार्थी के पिता औमप्रकाश थी। अप्रार्थी सं० 1 के नाम दर्ज आराजी प्राथर्जी व अप्रार्थीगण सं० 1 ता 2 व दावामें प्रतिवादीगणसं० 3 व 4 की जददी जायदा द है जिसमें प्राथ्र एवं दावा के सभी प्रतिवादीगण का जन्म से हक व अधिकार है। प्रतिवादीगण सं० 3 व 4 ने ने शुरू से ही अपना हक हिस्सा त्याग कर हिस्सा शून्य कर लिया है। वाद भूमि अप्रार्थी के नाम दर्ज रहने से अप्रार्थी वाद भूमि को बहकावे में आकर रहन/बैय या मुन्तकिल करने पर आमादा है यदि वह अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो इससे प्रार्थी को अपूर्ण्य क्षति होगी। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अपीलाधीन निर्णय के द्वारा खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट का प्रश्नगत भूमि में हक हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत है विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट का हक ना होने सम्बन्धित कोई अवधारण पारित नहीं की। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन अपूर्ण्य क्षति के बिन्दू रेस्पोजेण्ट के पक्ष में करने में भूल की है क्यों कि संयुक्त हिन्दू खानदान की पैतृक सम्पति में जन्म से हक व हिस्सा प्रथम दृष्टया अपीलांटा का है। इस कारण सह काशत कार भूमि में से सिंचाई व्यवस्था भंग करने का किसी भी काशतकार को एकल रूप से कोई अधिकार नहीं है। प्रथम दृष्टया प्रकरण रेस्पोजेण्ट सं० 1 के हक में नहीं बनता है एवं सिंचाई व्यवस्था भंग होने से फसल को पानी की आपूर्ति पर्याप्त मात्र में नहीं होने से क्षति होने की

Law

राजस्व अपील प्राधिकारी

सम्भावना अत्यधिक होने से सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू भी अपीलान्ट के पक्ष में है एवं भूमि को अगर दौराने वाद रहन बेय एवं मुन्तकिल किया जाता है तो भी दावा के रोज की स्थिति परिवर्तित होने की सम्भावना एवं प्रकरणों की बाहूल्यता बढ़ने की सम्भावना होगी ऐसी स्थिति कें अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोजेण्ट संख्या 1, 2 ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्नगत वर्णित वाद भूमि सम्पूर्ण खतोदारी प्रार्थी के दादा श्योचंद की खातेदारी नहीं हुआ करती थी। वाद भूमि में मिन अप्रार्थी की स्वअर्जित भूमि भी शामिल हैं इसलिए सम्पूर्ण भूमि में प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा अपीलान्ट ने दावा में प्रतिवादीगण सं0 3 व 4 द्वारा वाद भूमि में अपना हक व हिस्सा प्रार्थी के पक्षमें तर्क कर अपना हक व हिस्सा शून्य होना गलत अंकित किया है व प्रार्थी को वाद भूमि में 1/3 हिस्सा पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। रेस्पोजेण्ट जिस भूमि में कुआ व ट्रांसफमर लगा रखा है वह उसकी खुद की स्वअर्जित खातेदारी है। अप्रार्थी के खेत में लगे कुआ का पानी खराब हो गया एवं सिंचाई लायक नहीं रहा जिसके चलते अप्रार्थी अपने दूसरे खेत में कुआ लगा रहा है जहां अप्रार्थी अपने पुराने बिजली कनेक्शन की नियमानुसार स्थानान्तरित करवा रहौ जिसे रूकवाने का प्रार्थी को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। यदि प्रार्थी को बिजली कनेक्शन की आवश्यकता है तो बिजली विभगा से नियमानुसार अपना कनेक्शन लेने हेतु स्वतंत्र है परन्तु अप्रार्थी का अपने कनेक्शन को दूसरे खेत में स्थानान्तरित करने से रूकवाने का प्रार्थी को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। अपीलान्ट ने महज रेस्पोजेण्ट को नाहक हैरान परेशान करने के लिए यह प्रार्थना-पत्र पेश किया है। विचारण न्यायलाय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

5. रेस्पोजेण्ट संख्या 3 व 4 ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपीलान्ट/प्रार्थी ने औमप्रकाश के वारिस के तौर पर प्रश्नगत भूमि में खातेदारी अधिकारों का दावा किया है। वाद भूमि में रेस्पोजेण्ट/अप्रार्थी की स्वअर्जित भूमि भी

राजल्ल अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़



शामिल है। इसलिए सम्पूर्ण भूमि में अपीलान्ट का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अपीलान्ट ने प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 द्वारा वाद भूमि में अपना हक व हिस्सा प्रार्थी के पक्ष में तर्क करने का कथन किया है ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। अपीलान्ट का वाद भूमि में 1/3 हिस्सा पर कोई कब्जा काश्त हो ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। रेस्पोजेण्ट ने जिस खेत में कुआ व ट्रांसफार्मर लगा रखा है वह उसकी खुद की स्वअर्जित खातेदारी है व रेस्पोजेण्ट के खेत में लगे कुआ को पानी खराब होने के कारण स्थानान्तरित करवा रहा है जिसे रूकवाने का अपीलान्ट को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। यदि अपीलान्ट को बिजली कनेक्शन की आवश्यकता है तो बिजली विभाग से नियमानुसार अपना कनेक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है परन्तु रेस्पोजेण्ट को अपने कनेक्शन को दूसरे खेत में स्थानान्तरित करने से रूकवाने का उसे कोर्ट अधिकार नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला रेस्पोजेण्ट के पक्ष में है। यदि प्रकरण में अस्थाई निषेधारी जारी की जाती है तो वह अपनी भूमि के सुविधानुसार उपयोग उपभोग से वंचित हो जायेगा। यदि रेस्पोजेण्ट कुआ का कनेक्शन करवाना चाहता तो अपीलान्ट को किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। अपीलान्ट के खातेदारी हक अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में किया जाना है जो अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू अपीलान्ट के पक्ष में नहीं है बल्कि रेस्पोजेण्ट के पक्ष में है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलान्धीन निर्णय दिनांक 07.03.2022 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Leorio
24/12/22
(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़